पश्चिमी घाट पर मत्स्य पत्तनों की कमी

1622. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मत्स्य पोतों के लिए पत्तन-घाटों की कमी के कारण मछुआरों को हो रही गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए अरब सागर के पश्चिमी तट पर और अधिक मत्स्य पत्तनों की स्थापना करने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार ने गुजरात के पश्चिम तट पर पोरबन्दर, जामनगर और भावनगर में मत्स्य पत्तन की स्थापना करने पर विचार किया है अथवा करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) भारत के पश्चिमी तट पर भारत सरकार की सहायता से एक बड़ा मत्स्य पत्तन, तेरह छोटे मत्स्य पत्तन और 77 मछली उतारने के केन्द्रों का काम पूरा कर लिया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर मत्स्य नौकाओं को उतरने एवं लंगर डालने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक और बड़े मत्स्य पत्तन, 9 छोटे मत्स्य पत्तनों और 10 मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने जनवरी, 1990 में 276.00 लाख रुपए की लागत से पोरबन्दर में एक छोटे मत्स्य पत्तन की मंजूरी दी है तथा केन्द्रीय सहायता के रूप में 50 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध करा दिया है। पोरबन्दर का मत्स्य पत्तन प्रचालन में है।

भारत सरकार ने केन्द्रीय तटवर्ती अभियांत्रिकी (मत्स्य) संस्थान बंगलौर को जामनगर जिले में ओखा नामक स्थान पर एक मत्स्य पत्तन के विकास के उद्देश्य से एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। भावनगर में मत्स्य पत्तन के विकास के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Financial Assistance to Gujarat for Agricultural production

1623. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the financial assistance provided to the Government of Gujarat during the Eighth Plan for implementation of the various Centrally-sponsored schemes for increasing agricultural production in the state; and

(b) the number of farmers benefited as a result thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) The financial assistance provided to the Government of Gujarat during the Eighth Plan for implementation of various Centrally Sponsored Schemes for increasing the agricultural production in the State is given as per statement enclosed. (*See* below) It is difficult to quantify the number of farmers benefitted as a result of implementation of the scheme as benefits flow both directly and indirectly. However, as per information furnished by the State Government, 159190 farmers have been benefitted under the Horticulture Schemes.

Statement

Financial Assistance released to Gujarat during Eighth Plan

Sl. No.	Name of the Scheme	Amount released (Rs. in lakhs) 1992-93 to 1995-96
1.	Non-overdue Cover Scheme	76.00
2.	Agriculture Credit Stabilitsation Fund	10.00
3.	Investment in Debentures of LDBs	2851.28
4.	Failed Wells Compensation Fund Scheme	2.50
5.	Integrated Cereals Development Programme-Rice	192.39
6.	Integrated Cereals Development Programme-Wheat	111.39
7.	Inegrated Cereals Development Programme-Coarse Cereals	362.68
8.	Intensive Cotton Development Programme	219.36
9.	Sustainable Dev. of Sugarcane based Cropping System Areas	166.64